(b) The National Telecom Policy 1994 envisages provision of Telephone connections practically on demand by 31-3-97.

(c) and (b) Yes, Sir. Basic services are being opened to private sector to augmen the efforts of DOT in meeting the National Telecom. Policy 1994 objectives.

Conversion of Telephone Exchange in Muzaffarnagar into Electronic Exchange

1945. SHRIMATI MALTI SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone exchange in Muzaffarnagar (U.P.) is partially electronic ;

(b) whether it is also a fact that telephone users of the part of the telephone exchange which is not electronic are facing difficulties due to frequent breakdowns in telephone services ;

(c) if so, whether there is a proposal to convert the above telephone exchange into fully electronic ; and

(d) if so, when the above job is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The subscribers of non-electronic exchange are not getting as efficient service as these of electronic exchange.

(c) Yes, Sir.

(d) The non-electronic exchange is planned to be converted into electronic exchange Progressively during 1994-95 and 1995-96.

Postal System Out of Gear in Jaipur

1946. SHRI GAYA SINGH :
SHRI N. GIRI PRASAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Postal System out of gear in Jaipur" appearing in "The Hindu" dated the 29th November, 1994 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) what steps are proposed to be taken to appoint sufficient staff to make the postal delivery system efficient and prompt ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The postal system in Jaipur city was put to strain due to heavy receipt of mail during the last Diwali period. Adequate steps were taken by the local postal authorities for the disposal of the additional work.

(c) The workload of postal delivery staff is reviewed periodically and appropriate remedial measures are taken.

उत्पीड़ित टेलीफोन उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाना

1947. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीनों के दौरान जिला उपभोक्ता न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कतिपय अधिकारियों द्वारा कतिपय टेलीफोन उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित किया गया है, अतः क्षतिपूर्ति के रूप में निगम को उन्हें 5,000 रुपए देना होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने अब संबंधित व्यक्तियों को उक्त राशि का भुगतान कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाये गये निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनके दोष क्या-क्या थे और क्या सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जुलाई, 94 के बाद, पिछले कुछ महीनों में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में निम्नलिखित मामलों का निपटान किया गया है जिनमें 5000/-रु० का हर्जाना दिया गया है और इसे एम टी एन एल के संबंधित अधिकारियों से वसूल करने का निदेश दिया गया है :

	आदेश जारी करने की तारीख
सर्वश्री	
1. एन० के० तलवाड़ बनाम एम टी एन एल	8-7-94
2. नलिनी त्रिपाठी बनाम एम टी एन एल	8-7-94
3. आर० एम० वत्स बनाम एम टी एन एल	7-10-94

(ख) उपर्युक्त क्रम सं० 2 और 3 में उल्लिखित मामलों के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली में अपील लंबित है । क्रम सं० 1 पर उल्लिखित पार्टी को चेक द्वारा 5000/-रु० के हर्जाने का भुगतान कर दिया गया है ।